>

17.34 hrs.

Title: Regarding Rural Electrification under Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी इजाजत से मैंने जो एक अर्जेंट मैटर आज पेश किया है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से एक स्कीम लाई गई। उस स्कीम को तीन वर्ष हो गये। उस स्कीम के पहले जो कन्सर्निंग डिपार्टमेंट इलैक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पी.डी.सी. और पी.डी.डी. हैं, उन्होंने अपनी-अपनी स्टेट्स में जितने अनकवर्ड मोड़े थे, अनकवर्ड विलेजेज़ थे, जहां बिजली नहीं थी, उन सब ने उसके लिए काम किया।[R35] एक किताब बनी। इसके बाद जब राजीव गांधी विद्युतीकरण का प्लान बनकर गया, तो उसे यहां से एनएचपीसी को भेज दिया गया। एनएचपीसी ने उसे खुद एन्जिक्यूट नहीं किया। एनएचपीसी वहां की पोजीशन नहीं जानती है। एनएचपीसी ने उस टेंडर को लेने के बाद क्या किया? लार्सन एंड टुब्रो नाम की एक कंपनी है, उसे दे दिया। इस तरह से इसमें एक और ठेकेदार आ गया। पहले एनएचपीसी, फिर एलएंडटी और उसके बाद एलएंडटी ने भी आगे कांट्रैक्टर रख लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां काम होना था, जहां दस पोल लग सकते थे, जिसे कंसर्निंग स्टेट का डिपार्टमेंट चलाता, लेकिन अब वहां एक ही रहेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सप्लाइटेशन हो रही है, उससे इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, वह स्टेट पर पड़ेगा।

मेरी सबमिशन है कि इस तरह की जो पालिसीज बन रही हैं, जो कांट्रैक्टर्स को फायदा देने के लिए हैं, उनके बारे में हम सोचें। हमारा अपना इंजीनियर वहां बेकार है, वह इसे खुद कर सकता है। वह पोल भी लगा सकता है। लोकल लेबर का भी वहां बेड़ागर्क हो गया। मेरी रिक्वैस्ट है कि मेहरबानी करके इस तरह के जो प्लान किए जा रहे हैं, जिनसे अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है, इंप्लायमेंट नहीं बढ़ रहा है, इससे खर्च बढ़ रहा है और जो खर्च बढ़ेगा, वह देश पर बोझ है, स्टेट पर बोझ है। मेरी सबमिशन है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट इसके लिए काम करता है, जिन्होंने प्रोजेक्ट या प्लान बनाए हैं, उनको ही काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के बात मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।